By Speed Post

सत्यमेव जयते

No. Tour Report/5/Rajasthan/Member(HKD)/2017-RU-II
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
****

6th floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Date:- 11.10.2017

To

The Principal Secretary,
Tribal Area Development Department
Government of Rajasthan Secretariat,
Jaipur, Rajasthan.

Sub:- Tour Report from 12.07.2017 to 17.07.2017 of Shri H.K. Damor, Hon'ble Member, NCST to District- Udaipur and Pratapgarh, Rajasthan regarding inspection of boys and Girls' Schools and Hostels.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Tour Report from 12.07.2017 to 17.07.2017 of Shri H.K. Damor, Hon'ble Member, NCST to District- Udaipur and Pratapgarh, Rajasthan on the above mentioned subject.

2. It is, therefore, requested to furnish the requisite information/Action Taken Report on the above said Tour Report to the Commission at the earliest.

Yours faithfully,

Encl: As above

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director
Tel: 24641640

Copy to:-

1. The District Collector, District- Udaipur, Rajasthan -313001.
2. The District Collector, District- Pratapgarh, Rajasthan -312604.
3. SAS, NIC, for uploading on the website of the Commission.
4. C. Cell.

श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिनांक 12.07.2017 से 17.07.2017 तक राजस्थान राज्य के उदयपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों की राजकीय प्रवास रिपोर्ट।

1.	प्रवासित गणमान्य अथिति का नाम	श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य
2.	प्रवास की तिथी	12.07.2017 से 17.07.2017
3.	प्रवास स्थल	जिला मुख्यालय – उदयपुर एवं प्रतापगढ़, राजस्थान
4.	मुख्य व्यक्ति / कार्यालय / संगठन जिनसे मुलाकात की गई।	जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ एवं अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी
5.	यात्रा के मुख्य बिन्दु	यात्रा प्रवास का विवरण तिथीवार निम्नवत है।

दिनांक 13.07.2017

उदयपुर से सड़क मार्ग द्वारा प्रतापगढ़ के लिए प्रस्थान के उपरान्त मार्ग में बिखरी फैले जनजाति क्षेत्र में स्थित जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जनजाति बालिका छात्रावास, गुलाब कॉलोनी भींडर का निरीक्षण किया गया।

बालिका छात्रावास एकान्त में एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। प्रवेश द्वार पर झाडियाँ एवं विलायती बबूल उगे हुए है, जिसके कारण छात्रावास में प्रवेश दुर्गम हो गया है। प्रवेश द्वार के आस पास तत्कालझाडियाँ कटवा करसही कराने की आवश्यकता है। बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है, जिससे जगली जानवरों, बिच्छु, सांप तथा असामाजिक तत्वों को छुपने की जगह न मिल सकें।

छात्रावास पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि शैक्षणिक सत्र 2017–18 दिनांक 19 जून 2017 से प्रारम्भ हो चुका है, परन्तु छात्रावास के प्रवेश द्वार पर ताला लगा हुआ है। छात्रावास के आस–पास रहने वाले निवासियों से सम्पर्क करने पर पता चला कि छात्रवास अधीक्षिका (Warden) रेणु खरोसा, जो उदयपुर निवासी है तथा 19 जून से शैक्षणिक के प्रारम्भ होने के उपरान्त आज (13.07.2017) तक छात्रावास में उपस्थिति नहीं दी है।

शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त बालिकाएँ निवास हेतु छात्रावास में आई थी, परन्तु छात्रावास में खाद्य सामग्री की आपूर्ति नहीं होने के कारण पुनः वापस घर लौट गई है।उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु सदस्य महोदय द्वारा खाद्यान्न आपूर्तिकर्त्ता तथा परियोजना

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर से दूरभाष पर सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि जिला परिषद् द्वारा दिनांक 05.07.2017 को ही खाद्य सामाग्री की आपूर्ति का आदेश दिया गया है, परन्तु अभी तक आपूर्ति प्रारम्भ नहीं हुई है। सम्बन्धित ने दिनांक 16. 07.2017 तक खाद्य सामग्री की आपूर्ति का आश्वासन दिया। जिला परिषद् द्वारा छात्रावासों में आपूर्ति का आदेश शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व किया जाना चाहिये था। जिससे विद्यालय में प्रवेशित छात्राओं को छात्रावास में भोजन की व्यवस्था समय पर हो सके। शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त लगभग 25 दिन के बाद भी छात्रवास को सुचारू रूप से संचालित नही करना कार्य में लापरवाही बरतने का संकेत है।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शैक्षणिक छात्रावासों के कार्य संचालन के लिए एक कैलेण्डर बनाना चाहिये। अवकाश दिनों में मरम्मत एवं निर्माण का कार्य तथा शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व वार्डन (अधीक्षिका) एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवा कर सफाई व्यवस्था तथा भोजनालय की व्यवस्था करवानी चाहिये जिससे दूरस्थ स्थानों से आने वाले अदिवासी बच्चो को शैक्षणिक सत्र के प्रथम दिवस से ही छात्रावास की सुविधा मिल सकें।

तत्कालिन निरीक्षण में वार्डन एवं अन्य स्टाफ का छात्रावास में नहीं मिलना आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक अव्यवस्था का द्योतक है। छात्रावासों में विद्यार्थियों एवं स्टाफ की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बालिका छात्रावासों में वार्डन महिला ही है और छात्रावास परिसर में ही अपने आवास में निवास करें यह सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। जिससे अदिवासी क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार हो सकें।वर्तमान अव्यवस्थाओं से छात्राओं के अध्ययन में व्यवधान हो रहा है।

भरड़िया जनजाति बालक छात्रावास

उदयपुर जिले की भीण्डर पचांयत समिति में स्थित भरड़िया जनजाति बालक छात्रावास (माडा क्षेत्र) का भी निरीक्षण किया गया।

भरड़िया जनजाति बालक छात्रावास 12 वीं कक्षा के स्तर तक के विद्यार्थियो के लिए खोला गया है। निरीक्षण के समय छात्रावास अधीक्षक श्री हेमराज मीणा, रसोईया श्री बद्रीनारायण गर्ग एवं श्री शम्भूसिंह शक्तावत अनुपस्थित मिले। छात्रावास परिसर में श्री जसशंकर मीणा एवं श्री जीवन लाज रावत ही उपस्थित मिले।

निरीक्षण में पाया गया कि छात्रावास भवन के कुछ दरवाजे, फर्श एवं कुछ खिड़कियाँ टूट चुके है । अतः विभाग द्वारा इनकी तत्काल मरम्मत करवाई जानी चाहिए। शैक्षणिक सत्र् प्रारम्भ हो जाने के उपरान्त भी खाद्य सामग्री की आपूर्ति छात्रावासों में नहीं होना विभाग की लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण है।

छात्रावास की सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं पाई गयी। सभी लोहे के दरवाजे जगं लगने से खराब हो गए हैं, जबकि उन्हे पेंट करवा कर सही करवाया जा सकता है।

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

शौचालय के दरवाजे एवं सफाई भी खराब स्थिति में पाई गयी। शौचालय में टाईलें नहीं होने के कारण भी सफाई करवाया जाना सम्भव नहीं है। शौचालय खराब होने एवं अत्यन्त गंदे होने के कारण उपयोग योग्य नहीं हैं। शौचालय की टंकी छोटी होने के कारण भराव क्षमता भी कम है। छात्रावास के छात्रों को खुले में स्नान करना पड़ता है। जिसके कारण उसे बार –बार भरना पड़ता है। अतः शौचालयों के पूर्ण उपयोग हेतु सफाई व्यवस्था, मरम्मत तथा बड़ी क्षमता की टंकी लगाई जाने की आवश्यकता है।

इस छात्रावास में राजकीय सीनियर सेकण्डरी विद्यालय, सारणपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बेझड़ा एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माताजी का खेड़ा के विद्यार्थी निवास करने है परन्तु प्रवेश प्रकिया पूर्ण न होने, खाद्य आपूर्ति तथा मरम्मत कार्य नहीं होने के कारण अभी तक छात्रावास का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। जिसके कारण विद्यार्थियों से निरीक्षण के दौरान चर्चा नहीं हो सकी।

निरीक्षण के समय कार्मिको का छात्रावास पर नहीं मिलना एवं छात्रावास का संचालन नियमानुसार नहीं करना, कर्त्तव्यनिष्टा के प्रति लापरवाही का संकेत है। राज्य सरकार को तत्काल सुधार करने हेतु अनुवीक्षण व निरीक्षण प्रकिया को तत्काल प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

<u>उच्च प्राथमिक विद्यालय–बेझरड़ा</u>

दिनांक–13.07.2017 को माननीय सदस्य द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय–बेझरड़ा, पंचायत समिति– तहसील जिला का भी निरीक्षण किया गया है ।

निरीक्षण के समय प्रधानाध्यक श्री शशिकांत आमेटा एवं श्री उदयसिंह, अध्यापक विद्यालय से अनुपस्थित मिले। विद्यालय में प्रधानाध्यक सहीत कुल 5 पद स्वीकृत है। उसमें प्रधानाध्यापक एक अध्यापक का बिना अवकाश स्वीकृत कराये विद्यालय से अनुपस्थित होना कर्तव्य के प्रति लापरवाही का परिचायक है।

मध्यान्ह भोजन के सम्बन्ध में रसोई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी। जिसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। मध्यान्ह भोजन के लिए खाद्य सामग्री का संग्रहण जिस कक्ष में किया जा रहा है, उस कक्ष में बारिश का पानी गिर रहा है। छतः में बड़ी दरार है। जिसके कारण हादसा होने की भी सम्भावना है। खाद्य सामग्री भी खराब हो रही है। छत की तत्काल मरम्मत करावाया जाना नितान्त आवश्यक है। खाद्य सामग्री को सुरक्षित स्थान पर रखा जावे।

विद्यालय का एक कक्ष अनुपयोगी सामन से भरा हुआ है। अनुपयोगी सामान का नियमानुसार निस्तारण शीघ्रतिशीघ्र किया जाना आवश्यकत है। जिससे कमरे का उपयोग किया जा सके।

यह विद्यालय जनजाति क्षैत्र के गांव में स्थित है। जिसमें अधिकांशतः छात्र–छात्राऐं अनुसूचित जनजाति वर्ग से है। सदस्य महोदय द्वारा विद्यार्थियों से भी परिचय किया एवं

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

विद्यार्थियों के अध्ययन स्तर के मूल्यांकन बाबत् पठन कार्य भी करवा कर देखा। मूल्यांकन में पाया गया कि बच्चों का शैक्षणिक स्तर अन्यन्त ही कमजोर है। सातवी कक्ष के बच्चो को गणित के मूल सिद्धान्त जैसे जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग भी नहीं आता है। इस सम्बन्ध में शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि जनजाति वर्ग के विद्यार्थी अध्ययन कार्य में रूचि नहीं लेते है।

जिस पर सदस्य महोदय द्वारा शिक्षक को सुझाव दिया गया कि बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुसार अपनी शिक्षण पद्धति को मनोरंजक एवं रूचिकर बनाते हुए अध्यापन कार्य करना चाहिये। शिक्षण हेतु अध्ययन सामग्री को स्थानीय भाषा में अनुवाद कर स्थानीय भाषा में भी अध्यापन कार्य करवाया जाना चाहिये। जिससे बच्चे शिक्षण सामग्री को अच्छी तरह से समझ सकें।

आठंवी कक्षा में कुल 40 विद्यार्थियों का पंजीकरण है। जिसमें से केवल–5 बच्चे एवं सातंवी कक्षा में कुल 14 विद्यार्थियों का पंजीकरण है, जिसमे से केवल 5 विद्यार्थी ही उपस्थित थे। सदस्य महोदय द्वारा सभी शिक्षकों को शिक्षण कार्य में रूचि लेकर बच्चों के बौद्धिक स्तर को सुधारने का निरन्तर प्रयास करने हेतु सुझाव दिया।

आंगनबाड़ी केन्द्र, बेझरड़ा

सदस्य महोदय द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र, बेझरड़ा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आंगनबाड़ी में उसे 6 वर्ष तक के 12 बच्चे गणवेश में उपस्थित मिले। केन्द्र पर 4 धात्री महिलाऐं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहयोगिनी एवं आशा सहयोगिनी उपस्थित मिली। क्षैत्र की ANM भी बच्चों का टीकाकरण करते हुए मिली।

आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों के खेलने हेतु खिलौने नहीं है। सदस्य महोदय ने सुझाव दिया कि आगंनबाडी कार्यकर्त्ता प्रयास करके जनसहयोग से बच्चों के लिए बैग एवं खिलौने की व्यवस्था कर सकते है। केन्द्र पर शैचालय की व्यवस्था नहीं है। जिसके लिए विभाग को आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। आंगनबाड़ी केन्द्र की छतो एवं दीवारों की मरम्मत की जाने की आवश्यकता है।

आंगनबाड़ी केन्द्र वर्तमान में बस्ती से लगभग 1 किमी दूर बना हुआ है। जो कि सुरक्षा एवं छोटे बच्चों के आवागमन की दृष्टि से ठीक नहीं है। सदस्य महोदय ने सुझाव दिया कि भविष्य में आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण सदैव बस्ती के निकट ही करना चाहियें। जिससे बस्ती के अधिकांश बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके।

राजकीय एकलव्य उच्च माध्यमिक मॉडल आवासीय बालिका विद्यालय, टीमरवा

सदस्य महोदय द्वारा दिनांक – 13.7.2017 को ही राजकीय एकलव्य उच्च माध्यमिक मॉडल आवासीय बालिका विद्यालय, टीमरवा का भी निरीक्षण किया गया। इस आवासीय विद्यालय का प्रारम्भ वर्ष 2012 में किया गया है। इस आवासीय विद्यालय में कुल 300

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

छात्राओं के आवास की व्यवस्था है, जिसमें से वर्ष 2016–17 में 245 छात्राओं को प्रवेश दिया गया था। वर्ष 2012 में प्रारम्भ हुये इस विद्यालय में आज तक छात्रावास अधीक्षक एवं कोच के पद स्वीकृत नहीं हुये है। जिसके संदर्भ में विभाग द्वारा तत्काल पद स्वीकृत करवाने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना चाहिये। वर्तमान में श्रीमती यशोदा सोनी, सहायक अध्यापिका को अधीक्षक पद का दायित्व दे रखा है। निरीक्षण तिथि 13.7.2017 को उपस्थिति पंजिका में उपस्थित छात्राओं के हस्ताक्षर नहीं थे। आवासीय कक्षों का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि छात्राओं का सामान अस्त–व्यस्त पड़ा हुआ था। अध्यापिकाओं को चाहिये की वे सभी छात्राओं को अनुशासित एवं सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। खाली कमरों में भी ट्यूबलाईटे जल रही थी। व्यर्थ बिजली न जले और व्यर्थ पानी न बहे। यह भी देखा जाना चाहिये।

विभाग को कमरों के बाहर जूतों के स्टैण्ड की भी व्यवस्था करनी चाहिये। पेय जल के संधारण के लिए फिल्टर की व्यवस्था करनी चाहिये। वर्तमान में पेय जल के पात्र बिना ढ़क्कन के रखे हुये थे। इस व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है। शौचालय एवं स्नानघर के कुछ वॉशबेसिन खराब पड़े हुए है। छात्रावास के रसोईघर तथा अन्य व्यवस्थाऐं संतोषजनक स्थिति में पाई गई। विद्यालय के कार्मिक परिसर में उनके लिए बने ''आवास गृहों'' का उपयोग नहीं कर रहे है। नियमानुसार उनके छात्राओं को उनके लिए बने आवासगृहों में ही रहना चाहिए।

सदस्य महोदय द्वारा छात्राओं से भी वार्तालाप किया गया। सदस्य महोदय ने विद्युत एवं जल के संरक्षण हेतु प्रेरित किया। सदस्य महोदय ने छात्राओं के सम्बोधन में उच्च शिक्षा ग्रहण कर प्रशासनिक अधिकारी/डाक्टर संस्कारवान बनने तथा पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त ही शादी के बन्धन में सही उम्र में बंधने की सलाह दी। उच्च कोटि के चरित्र निर्माण एवं नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया। सम्बोधन के अंत में संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति को प्रदत्त सुरंक्षणों एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सम्बन्ध में परिचय प्रदान किया।

विद्यालय का निरीक्षण करने पर पाया गया कि उपस्थिति पंजिका भी अधूरी मिली। छात्राओं से संवाद स्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि कुछ छात्राऐं अंग्रेजी विषय में अत्यन्त ही कमजोर है। वर्तमान में रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र तथा अंग्रेजी विषय अध्यापक के पद रिक्त है। ये सभी विषय महत्त्वपूर्ण है तथा बिना अध्यापक के अध्ययन किया जाना सम्भव नहीं है।

विगत शैक्षणिक सत्र में इस आवासीय विद्यालय का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम शत् प्रतिशत रहा है। दो छात्राओं ने तो गणित विषय में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विशेष योग्यता भी प्राप्त की है। सदस्य महोदय ने परीक्षा परिणाम में और सुधार लाने व अंको का प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया।

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krishna Damor
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(7)

राजकीय कन्या जनजाति खेल छात्रावास, प्रतापगढ़

माननीय सदस्य द्वारा राजकीय कन्या छात्रावास, प्रतापगढ़ का निरीक्षण करने पर पाया कि भवन, रसोईघर तथा पेय जल की व्यवस्था संतोषजनक है। छात्रावास में पेय जल संधारण हेतु आर. ओ. की भी व्यवस्था है। भोजन भी भोजन मीनू के अनुसार बनाया जा रहा है। आवास व्यवस्था का अवलोकन करने पाया गया कि एक कमरे में काफी नई स्कूटियां रखी हुई है। यह नई स्कूटियाँ प्रतिभावान छात्राओं को वितरित करने हेतु काफी समय से रखी गई है। इनको शीघ्रतिशीघ्र वितरित किया जाना चाहिए। जीमसैट बाहर खुले में रखा हुआ है।

छात्राओं से सम्बन्ध स्थापित होने पर पता चला कि छात्राओं का सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी एवं गणित का बौद्धिक स्तर उनके कक्षास्तर से न्यून पाया गया।

राजकीय बालक जनजाति खेल छात्रावास, प्रतापगढ़

माननीय सदस्य द्वारा राजकीय बालिक जनजाति खेल छात्रावास, प्रतापगढ़ का निरीक्षण किया गया। इस छात्रावास में कुल 50 बालकों की प्रवेश क्षमता है। सभी सीटो पर प्रवेश दिया गया है। खेल छात्रावास के छात्रों ने तीरन्दाजी में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया है। छात्रावास भवन, रसोईघर तथा अन्य व्यवस्थाऐं सन्तोषजनक पायी गयी।

वर्तमान समय में छात्रों को तकिया एवं ओढ़ने हेतु खेस उपलब्ध नहीं कराया गया हैं। जीमसैट का उपभोग नहीं किया जा रहा है। कमरों में सामान अव्यवस्थित पाया गया। छात्रावास के भवन के एक भाग में पानी टपक रहा है। छात्रावास के मैदान का समतलीकरण नहीं होने के कारण वर्तमान में खेल मैदान का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

दिनांक – 14.7.2017

राजकीय आर्दश उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपलखूंट

माननीय सदस्य महोदय द्वारा राजकीय आर्दश उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपलखूंट का निरीक्षण किया गया। प्रधानाचार्य का पद रिक्त है । निरीक्षण के समय कार्यवाहक प्रधानाचार्य के समय पर विद्यालय नहीं आने की शिकायत प्राप्त हुई। । निरीक्षण के समय विद्यालय के कार्मिक, व्याख्याता रसायन विज्ञान, राजनैतिक विज्ञान भी अनुपस्थित मिलें।

कक्षा के कमरों में प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं है। कुछ कक्षाओं में छात्र/छात्राओं की संख्या अधिक है फिर भी एक ही कक्ष में बैठाया गया है, जबकि कुछ कमरे खली पडे हैं। श्यामपट्ट पर लिखा हुआ पीछे बैठें छात्र/छात्रों को ठीक तरह से दिखता नहीं है। नाम आदर्श विद्यालय है परन्तु अव्यवस्थाएं ही अधिक हैं। यह सब स्थानीय कार्मिकों की ही लापरवाही का प्रतीक है। विद्यालय प्रांगण में जगह – जगह पर झाड़ियाँ एवं घास उगी हुई है। विद्यालय भवन के रख–रखाव की उचित व्यवस्था नहीं पाई गयी। मध्यान्ह भोजन लकड़ियो के चूल्हे पर किया जा रहा है, गैस टंकीयाँ खाली पड़ी थी। राशन सामग्री आज ही समाप्त हो जाना बताया गया। जिसके तत्काल व्यवस्था की आवश्यकता है। वर्तमान में

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भोजन साप्ताहिक मीनू के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है। बच्चों को परोसा गया मध्यान्ह भोजन भी अच्छी तरह से पका नही था।

राजकीय आश्रम छात्रावास बालक – पीपलखुंट

राजकीय आर्दश उच्च माध्यमिक विद्यालय के उपरान्त राजकीय बालक आश्रम छात्रावास – पीपलखुंट का निरीक्षण किया गया । छात्रावास भवन की सफाई व्यवस्था सन्तोषप्रद नहीं पाई गई। कुछ छात्रों ने अपने बर्तन भी बिस्तर पर रख रखे थे व कुछ के बिस्तर के नीचे। जीमसैट खराब पड़ा हुआ था। शैचालयों में भी सफाई की उचित व्यवस्था नहीं थी। कुछ वाशवैल भी खराब पड़ै हुये थे।

रसोई घर की सफाई व्यवस्था भी संतोषप्रद नहीं थी तथा राशन सामग्री की गुणवता भी उत्तम स्तर की नहीं पाई गई। जनजाति विकास विभाग के अधिकारियों को समय – समय पर औचक निरीक्षण करना चाहिये तथा राशन की गुणवता को देखना चाहिये। जिससे व्यवस्था में सुधार हो सके।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपलखुंट

सदस्य महोदय द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपलखुंट का भी अवलोकन किया गया। निरीक्षण के समय डॉ. आर. एन. सीसोदिया, प्रभारी चिकित्सक अनुपस्थित मिले। दो अन्य कार्मिक भी अनुपस्थित मिले। सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। औषधी तथा अन्य

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव मिला। आवारा पशु चिकित्सालय परिसर में घूम रहे थे। राज्य सरकार को तत्काल सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की आवश्यकता है।

बालविकास परियोजना कार्यालय, पीपलखुंट

बाल विकास परियोजना कार्यालय, पीपलखुंट का निरीक्षण करने पर सामग्री अस्त–व्यस्त पड़ी मिली। एक महिला पर्यवेक्षक, सविता राजपूत का प्रवास पर जाने की सूचना मिली। कार्यालय रिक्त होने के कारण अन्य सूचनायें प्राप्त नहीं हो सकी। परियोजना अधिकारी प्रतापगढ़ बैठक हेतु गये होना बताया गया।

सदस्य महोदय द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र, चिकली (जैतलीय) भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन वर्षा में टपकता हुआ मिला। श्रीमती रकमी बाई, सहायिका ही केंद्र पर उपस्थित थी, बच्चे अनुपस्थिति मिलें। भवन काफी पुराना है। बच्चों को ठीक तरह से बैठने व खेलने की भी जगह नही है।

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krishna Da
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tri
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

आंगनबाड़ी केन्द्र ''करबलिया'' (पीपलखुंट) अपरान्ह 12.10 पर ही बन्द मिला। जिसके कारण निरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी।

माँ–बाड़ी डे केयर, छोटीखेड़ी (मोटी खेड़ी)

निरीक्षण के दौरान डे–केयर की सभी व्यवस्थाऐं संतोषजनक पाई गई, परन्तु छात्रों के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था नहीं है। कक्षा में अध्यापक को अध्यापन कार्य करवाते हुए पाया गया। अध्यापक ने अपनी टेबल पर एक बेंत बच्चों को अनुशासन में रखने हेतु रखी थी। परन्तु छोटे बच्चों को प्यार से ही समझाना चाहिए, उनको डरा कर नही। डर के कारण से बच्चे स्कूल आना छोड़ देते हैं।

दोपहर बाद 3:00 बजे जिला कलक्टर के अन्य जरूरी कार्य में व्यस्त होने से 2:30 बजे सर्किट हाऊस में मा. सदस्य से मुलाकात कर जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं एवम् उसमें प्रगति की संक्षिप्त जानकारी दी। उनके द्वारा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये किये गये विशेष प्रयासों का भी उल्लेख किया।

प्रतापगढ़ जिला स्तर अधिकारियों की अनुसूचित जनजाति के लिए क्रियान्वित की जा रही विकास योजनाओं के मूल्यांकन की बैठक।।

दिनांक 14.07.2017 को दोपहर 3:00 बजे श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली की अध्यक्षता में जनजाति कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत्रिंत विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में विभिन्न स्तर के अधिकारयिों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिये गये निर्णयों की कार्यवाही विवरण निम्ननुसार हैः–

01. **परिचयः**– बैठक में उपस्थित समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों से सामान्य परिचय लिया जाकर बाद अपना माननीय सदस्य द्वारा अपना परिचय दिया गया। जिसमें अपने कार्यकाल एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों को सरल रूप से दर्शाया गया। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग व उसके द्वारा संपादित कार्यो की भी संक्षिप्त जानकारी दी।

02. वन विभागः–बैठक में उपस्थित वन विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008–12 के अन्तर्गत कुल 6655 प्रकरणों की सख्यां है जिसमें वन्यजीव सीतामाता के प्रकरण 584 कुल 7239 प्रकरण है। जिला प्रतापगढ़ का वन क्षेत्र 34872.80 (हैक्टयर में) फैला हुआ है। जिसमें एसटी (आदिवासी) की संख्या 1238 एवं 2877.9024 है. में क्षेत्र फैला हुआ है।

03. उद्योग विभागः– बैठक में उपस्थित वन विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार, अन्य महिला, विशिष्ट योग्यजन, एससी एवं एसटी के कुल 99 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें एसटी के 35 आवेदन

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयो
National Commission for Scheduled
भारत सरकार/Govt. of Indi
नई दिल्ली/New Delhi

11

प्राप्त हुए है। 32 में से 9 आवेदनों पर बैकों से ऋण हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं 5 को ऋण वितरित भी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में वर्ष 2015–16 में 19, 2016–17 में 9 एवं वर्ष 2017–18 में 3 एसटी के कुल आवेदन प्राप्त हुए है।

04. कोष विभागः– बैठक में उपस्थित कोष विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में कुल बुजुर्ग, विधवा एवं रोगग्रस्त 89536 पेंशनधारी है। जिसमें से एसटी के कुल 19219 पुरष एवं 31108 महिला कुल 50327 पेंशनकर्ता है।

05. लीड बैंकः–बैठक में उपिस्थत लीड बैंक के मैनेजर ने अवगत कराया कि 1168.75 करोड़ रू. के लोन वर्तमान में चल रहे है जिसमें से 34.70 करोड़ रू. का लोन एसटी के लोगो को दे रखा है और समय पर टारगेट पुरे हो रहे है। रिकवरी में दिक्कते आ रही है।

06.उद्यान विभागः– बैठक में उपस्थित उद्यान विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में राज्य योजना में सब्जी प्रदर्शन, बांस मिशन में क्षैत्र संधारण, आरकेवीवाई में नया बगीचा, बगीचा संधारण, मसाला फसलो की खेती, वर्मी कम्पोस्ट, सौर उर्जा पम्प, पीएकेएसवाई में ड्रीप क्लोल, मिन्नी फव्वारा एवं फव्वारा संयत्र योजना का कार्य किया जा रहा है। बांस मिशन में 56 है. क्षैत्र में एसटी वर्ग के कृषक लाभान्वित हो रहे है।

07. सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभागः– बैठक में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाश्रम पेंशन योजना के अन्तर्गत 22127, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत 3997, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विशेष योग्यजन पेंशन योजना के अन्तर्गत 597, राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 48432, राज्य विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत 8400 एवं राज्य विर्शष योग्यजन पेंशन योजना के अन्तर्गत 5978 को लाभान्वित जा रहा है।जिले में कुल 13 छात्रावासों की संख्या है जिसमें से कुल स्वीकृत क्षमता 760 एवं वर्ष 2017–18 में प्रवेशित करने वाले छात्रों की संख्या 567 है।

08. ग्रामीण आजिविकाः–बैठक में ग्रामीण आजिविका विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि ट्रैनिंग के कार्य पीपलखूटं एवं अरनोद 2 ब्लॉको पर चल रहा है। 213 गांवो पर कार्य चल रहा है जिसमें से 23155 लाभान्वित परिवार है। माण्डना कलां से भी कई बेरोजगारों को रोजगार आदि का कार्य मिल रहा है।

09. कृषि विज्ञान केन्द्रः– बैठक में कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारी ने अवगत कराया कि विभाग में कुल स्वीकृत पद में कार्यरत के मुकाबले रिक्त पद अधिक है। कृषको को प्रशिक्षण का कार्य समय पर दिया जा रहा हैं एवं मधुमक्खी पालन का कार्य भी किया जा रहा है।

10. सार्वजनिक निर्माण विभागः– बैठक में उपस्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि विभाग में कुल 39 पद स्वीकृत है जिसमें से 15 पद कार्यरत है एवं 24 पद रिक्त है एवं खण्ड में 43 पद कुल स्वीकृत है जिसमें से 12 पद कार्यरत है 31 पद

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Da..
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tri..
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

रिक्त है। सड़के एवं बिल्डिंग का कार्य समय पर किया जा रहा है। जिसकी गुणवता में सुधार की आवश्यकता है।

11. खेलकूद विभागः– बैठक में उपस्थित खेलकूद विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि 1 करोड़ रू. की लागत से स्टेण्डियम का कार्य किया जा रहा है । जिले ने तीरंदाजी खेल के अन्तर्गत कई मैडल जिते है। औलम्पिक में भी इस खेल को खेला गया है।

12. श्रम विभागः– बैठक में उपस्थित श्रम विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत 458, शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत 498, प्रसूति सहायता योजना के अन्तर्गत 366, विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत 1683, साईकिल सहायता योजना के अन्तर्गत 256 दुर्घटना/मृत्यु सहायता योजना के अन्तर्गत 37 एवं टूलकिट सहायता योजना के अन्तर्गत 01 में लाभान्वित किया गया। 32000 से अधिक पंजीयन कर लिए गए है। जिसमें से 3299 लोगो को लाभान्वित किया जा रहा है।

13. शिक्षा विभाग (मा.):– बैठक में शिक्षा विभाग (मा.) के अधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में 60 प्रतिशत वेकेन्सी निकाली गई थी जिसमें से 40 प्रतिशत वेकेन्सी की पूर्ति की जाकर कार्य चलाया जा रहा है। थर्ड ग्रेड एवं सैकेण्ड ग्रेड टिचर की कोई कमी नहीं है।

14. शिक्षा विभाग (प्रा.):–बैठक में शिक्षा विभाग (प्रा.) के अधिकारी ने अवगत कराया कि 320 प्राथमिक स्कूल स्वीकृत है जिसमें से 111 कार्यरत है तथा 209 पर रिक्त है।

15. सहकारिता विभागः–बैठक में सहकारिता विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि भू–विकास केन्द्र की स्थिति पहले से अच्छी है एवं भू–विकास केन्द्र बैंक द्वारा लोन का कार्य भी किया जा रहा है। जिले में गत माह 7 योजनाओं में 10 लाभान्विता को ऋण दिया गया एवं इस माह 7 योजनाओं में 13 लाभान्वितो को ऋण दिया गया। जिले में वर्ष 2017–18 में प्रस्तावित ऋण वितरण की सख्यां 52 है जिसकी राशि 13.10 लाख रू. है।

16.कृषि विभागः–बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में कृषि विभाग कुल 135 पद स्वीकृत है जिसमें से 43 पद कार्यरत है एवं 92 पद रिक्त है। आत्मा योजना के अन्तर्गत जिले में 20 पद स्वीकृत है जिसमें कोई भी पद कार्यरत नही है एवं 20 ही पद रिक्त है।

17.विद्युत विभागः–बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि वर्ष 2016.17 में एसटी परिवारों को 1467 कृषि कनेक्शन दिये गये तथा वर्ष 2017–18 में माह जून तक 144 कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके है। जिले में 38 ढाणियों का विद्युतिकरण किया गया तथा वन क्षेत्र जहां सोलर से विद्युतिकृत करना के अन्तर्गत 47 गांव मे सोलर से विद्युतिकृत करना के अन्तर्गत 47 गांव मे सोलर होम लाईटिंग सिस्टम द्वारा कनेक्शन किया गये है अब तक सर्वे 2273 परिवारों में से 1500 कनेक्शन जारी कर दिये गये ह

18. साक्षरता विभागः–बैठक में साक्षरता विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 प्रयवेक्षक लगे हुए है जो राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी के साथ साथ निरक्षरों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में अब तक 60000 निरक्षर को जोड़ने का प्रयास किया जा चुका है । जिले में कुल 567848 जनसंख्या है

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(13)

जिसमें से 307134 पुरष एवं 182439 महिला साक्षर है। जनसंख्या के मुकाबले 56.30 प्रतिशत ही लोग साक्षर है।

19. चिकित्सा विभागः—बैठक में चिकित्सा विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में राजपत्रित अधिकारियों के 46 पद स्वीकृत है जिसमें 22 पद कार्यरत है एवं 24 पद रिक्त है। अराजपत्रित अधिकारियों के 211 पद स्वीकृत है जिसमें 140 पद कार्यरत है एवं 71 पद रिक्त है।

20. महिला अधिकारिता विभागः—बैठक में महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में वर्ष 2017—18 में 10 बाल विवाह रूकवाये गये थे जिसमें से 4 जनरल वर्ग के थे एवं शेष 6 एसटी वर्ग के थे जिले में 165 पद स्वीकृत है एवं 139 पद कार्यरत है एवं 26 पद रिक्त है।

21.खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागः—बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में कुल 345 उचित मूल्य दुकानकार कार्यरत है। खाद्य सामग्री का वितरण पॉश मशीन के माध्यम से किया जा रहा है जिले में 3 स्थानों पर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से पॉश मशीन कार्य नहीं कर पा रही है इसलिए खाद्य सामग्री का वितरण रजिस्टर के माध्यम से किया जा रहा है।

22. पुशपालन विभागः—बैठक में पुशापालन विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में कुल 110 पद स्वीकृत है जिसमें 48 पद डॉक्टर के पद स्वीकृत है जिसमें 14 पद डॉक्टर कार्यरत है शेष पद रिक्त हैं।

23. सीडीपीओ विभागः—बैठक में सीडीपीओ विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में 1239 आंगनबड़ी स्वीकृत है जिसमें से 1078 आंगनबाड़ी कार्यरत है एवं 161 आंगनबाड़ी रिक्त है। जिले में कुल 23 बच्चे कुपोषित है। समय पर कुपोषण का टिका लगाया जा रहा हैं।

24. राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम :— बैठक मे राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम के अधिकाारी ने अवगत कराया कि जिले मे कुल 1672 लाभान्वितो को प्रशिक्षण दिया गया है। जिसमें से 403 लाभान्वितो को रोजगाार दिया गया। गणेशपुरा, धरियावद एवं धमोत्तर पर जिले में 3 स्कीम डवलपमेंट का कार्य चल रहा ळें

25 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः— बैठक में उपस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में कुल 27 पद स्वीकृत है जिसमें से 7 पद कार्यरत है एवं 20 पद रिक्त है। जिले में कुल स्वीकृत सीट 204 एवं प्रवेश किये गये 203 है वर्तमान में अध्ययनरत छात्र 153 है। बॉश ब्रीज कोर्स के अन्तर्गत इसे संस्थान में 3 बैच चल रहा है जिसमें 25 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बैठक के अन्त में सदस्य महोदय द्वारा सभी अगुन्तक अधिकारियों के धन्यवाद देते हुए प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। शिक्षा विभाग एवम् चिकित्सा विभाग में रिक्त पद काफी हैं इस पर चिंता व्यक्त की तथा इन पदों को शीघ्र भरने के लिए प्रयास करने हेतु

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krishna Damor
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

सुझाव दिया। बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन **अनुलग्नक – 1** पर सलंग्न है।

राजकीय आश्रम छात्रावास बालक, धमोत्तर

माननीय सदस्य महोदय द्वारा राजकीय बालक आश्रम छात्रावास, धमोत्तर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि छात्रावास के गोदाम में पानी टपक रहा है। अधीक्षक ने प्लास्टिक लगाकर कर अस्थाई व्यवस्था कर रखी है। छात्रावास के भोजन कक्ष (डाईनिंग हॉल) में भी पानी टपक रहा है। शौचालय छात्रों के कमरों से काफी दूरी पर बने हुई है तथा छात्रावास परिसर में घास एवं झाड़ियाँ उगी गई है। रात्रि में शौचालय के उपयोग हेतु अधेंरे में जाना पड़ता है। जो कि सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। छात्रावास परिसर में साफ सफाई एवम् उचित प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता है।

छात्रों से संवाद करने पर ज्ञात हुआ कि छात्रों का कक्षानुसार कक्षा के स्तर के अनुसार संस्कृत एवं अंग्रेजी का ज्ञान कोचिंग नहीं है। इसमें सुधार हेतु छात्रावास में अतिरिक्त कक्षाओं एवं विषय अध्यापकों की व्यवस्था कर कोंचिग की जानी चाहिये।

अन्य व्यवस्थाऐं संतोषप्रद पाई गयी।

राजकीय कन्या छात्रावास, धमोत्तर

इस छात्रावास का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में छात्रावास अधीक्षिका का पद रिक्त है। प्रतापगढ़ अधीक्षिका को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। निरीक्षण के समय अधीक्षिका उपस्थित नही मिली।

छात्रावास के शौचालयों में सफाई व्यवस्था उचित नहीं होने के कारण गन्दगी फैली हुई थी। शैचालयों में विद्युत एवं जल की आपूर्ति भी ठीक नही है। जिसको तत्काल ठीक कराने की आवश्यकता है। छात्रावास में 50 छात्राओं के प्रवेश स्वीकृत है परन्तु वर्तमान में 24 छात्राओं को ही प्रवेश दिया गया है।

दिनांक – 15.7.2017

राजकीय कन्या छात्रावास, देवगढ़

सदस्य महोदय द्वारा दिनांक – 15.7.2017 को राजकीय कन्या छात्रावास, देवगढ़ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अधीक्षिका छात्रावास से अनुपस्थित मिली। छात्रावास की सफाई व्यवस्था असंतोषप्रद पाई गयी। छात्राओं के कमरों में सामान अव्यवस्थित मिला। छात्राओं के उपस्थिति रजिस्टर में भी हस्ताक्षर नहीं पाये गये। कन्या छात्रावास में अधीक्षिका का उपस्थित नही रहना उचित नही है। जानकारी करने पर बताया गया कि वह प्रतापगढ़ ही रहती है। दिन में कभी कभी आती है। इस व्यवस्था को बदलना आवश्यक है।

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krishna Damor
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for ...
भारत सरकार / G...
नई दिल्ली

राजकीय बालक आवासीय छात्रावास, देवगढ़

सदस्य महोदय द्वारा राजकीय बालक छात्रावास, देवगढ़ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अधीक्षिक छात्रावास में उपस्थित मिला। छात्रावास की सफाई व्यवस्था संतोषप्रद पाई गयी। वर्तमान में छात्रावास के नवीन भवन का कार्य चल रहा है। छात्रावास का परीक्षा परिणाम सन्तोषप्रद है, परन्तु प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कम होने के कारण सदस्य महोदय द्वारा अध्यापकों को अतिरिक्त समय देकर परीक्षा परिणाम की गुणवता में सुधार हेतु निर्देशित किया। वर्तमान में अधिकांश छात्र छात्रावास से अनुपस्थित चल रहे है। इसको सुधारा जाना आवश्यक है।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जेलदा

माननीय सदस्य द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जेलदा का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के समय श्रीमती लक्ष्मण झाला, अध्यापिका उपस्थित मिली। अध्यापिका ने अवगत कराया कि विद्यालय में 56 विद्यार्थी प्रवेशित है, जिनमें से 52 उपस्थिति मिले। विद्यालय में अध्यापक के 2 पद स्वीकृत हैं। जिसमें से एक पद रिक्त है।

सदस्य महोदय द्वारा बन रहे मध्यान्ह भोजन का भी निरीक्षण। भोजन की गुणवता अच्छी पाई गयी। विद्यालय के छात्रो का सामान्य ज्ञान संतोषजनक पाया गया तथा विद्यालय की अन्य व्यवस्थाऐं भी उचित एंव सुव्यवस्थित रूप में मिली।

राजकीय अम्बेडकर बालक छात्रावास, धरियावाद

सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इस छात्रावास की स्वीकृत संख्या – 115 है तथा वर्तमान में 107 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। जिसमें से 71 छात्र निरीक्षण के समय उपस्थित मिलें। निरीक्षण के समय एक छात्र बीमार मिला।

छात्रावास की सफाई व्यवस्था सन्तोषप्रद मिली। शैचालयों की सफाई अच्छी नहीं थी। शैचालय का एक ब्लॉक लम्बे समय से बंद पड़ा है, जिसको तत्काल चालू करवाने की आवश्यकता है। छात्रावास के गद्दे एवं चद्दर पुराने हो गये है। स्नानघर कि व्यवस्था सही नहीं होने के कारण छात्र बाहर ही स्नान करते है।

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krishna Damor
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

वर्ष 2016–17 में कक्षा 11 का परिणाम शत प्रतिशत रहा। जिसमें से 06 छात्र प्रथम श्रेणी में तथा 06 छात्र द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुये। कक्षा दसवी के तीन छात्र प्रथम श्रेणी में तथा तीन छात्र द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुये है, शेष 2 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुये है। छात्रावास की प्रवेश प्रक्रिया अभी तक अपूर्ण है तथा अन्य सुविधाऐं संतोषजनक पाई गयी।

राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास, धरियावाद

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित इस छात्रावास में कुल 70 छात्राओं के प्रवेश की व्यवस्था है तथा 70 छात्राओं को प्रवेश दिया जा चुका है। गत शैक्षणिक वर्ष में कक्षा बाहरवीं का परीक्षा परिणाम 93 प्रतिशत रहा, जिसमें से प्रथम श्रेणी में 3 छात्राऐं उत्तीर्ण हुई। दसवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम शत् प्रतिशत रहा। प्रथम श्रेणी छात्राओं की संख्या कम होने पर सदस्य महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए परीक्षा परिणाम की गुणवता में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

दिनांक – 17/7/2017

आयुक्त कार्यालय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के साथ जनजाति उपयोजना क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विकास योजनाओं के मूल्याकंन बैठक।

सर्वप्रथम आयुक्त द्वारा सदस्य महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली का स्वागत किया गया। तत्पश्चात अधिकारियों से परिचय उपरांत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना एवं कार्य प्रणाली के बारे में अवगत कराया। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र विस्तार हेतू प्रेषित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र विस्तार हेतु 642 ग्राम एवं 3 नगरीय क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा केबिनेट से अनुमोदन पश्चात भारत सरकार को प्रेषित प्रस्तावों पर अब तक हुई प्रगति से अवगत कराया गया तथा भारत सरकार से इसे शीघ्र अधिसूचित करवाने हेतु निवेदन किया गया।

माननीय सदस्य महोदय द्वारा वनाधिकार अधिनियम एवं पीसा एक्ट का जनजाति क्षेत्र में प्रभावी कियान्वयन करने हेतु निर्देशित किया गया। वनाधिकार अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की योजना में प्रगति संतोषप्रद है, परन्तु सामुदायिक वनाधिकार पत्रों पर समुचित प्रगति नहीं हुई है। अतः निर्देशित किया गया कि सामुदायिक वनाधिकार पट्टे जारी किये जाने पर भी विशेष ध्यान दिया जावे। इस हेतु समुचित प्रचार प्रसार किया जावे ताकि अधिकाधिक जनजाति व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सके।

माननीय सदस्य महोदय द्वारा पीसा एक्ट की भावना अनुसार जनजाति व्यक्तियों द्वारा एकत्रित की जाने वाली लघु वन उपाज संग्रहण (एमएफपी) तथा विपणन व्यवस्था की जाए ताकि अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इस हेतु प्रयास करने के निर्देश दियें।

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krishna Damor
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled T
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(17)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जावे जिससे जनजाति छात्र–छात्राओं का शिक्षा की ओर रूझान बढे। माननीय सदस्य महोदय द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का निरीक्षण किया गया उनमें नकारा सामग्री का निस्तारण, छत से पानी टपकने आदि समस्याओं के समाधान के निर्देश दियें।

प्रतापगढ जिले में संचालित मां–बाडियों के निरीक्षण के दौरान मां–बाडी/डे–केयर केन्द्रों पर खाद्यान्न एवं अन्य व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिये गये। जिला प्रतापगढ में क्रम की गई स्कूटीयों का वितरण शीघ्र कराने के निर्देश दिये गये।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निर्मित बंद पडी सामुदायिक जलोत्थान सिचाई योजनाओं को प्राथमिकता से प्रारंभ करने के निर्देश दिये। सहरिया एवं कथोडी जनजाति व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार तथा राजकीय सेवाओ में सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

जनजाति क्षेत्र में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में मिड–डे–मिल अन्तर्गत भोजन की गुणवत्ता, खाद्यान्न सामग्री की उपलब्धता एवं अध्यापकों की समय पर विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कुछ इलाकों में पानी में फ्लोराईड की मात्रा अधिक पाई जाती है। अतः शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। माननीय सदस्य महोदय द्वारा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं की अनुसूचित क्षेत्र में प्रगति के सबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

माननीय सदस्य महोदय द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर संतोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किय गया कि योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जावे।जिससे अधिकाधिक जनजाति के व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो सके।

जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से आए अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के द्वारा दिए गए ज्ञापनों पर भी चर्चा कर समुचित कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये।

बैठक के अन्त में माननीय सदस्य महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जनजाति विकास हेतु किये जा रहे प्रयासो की सराहना करते हुए और अधिक मेहनत करने की बात कही।

माननीय सदस्य महोदय के प्रवास के सम्बन्ध में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार अनुलग्नक – 2 पर सलंग्न है।

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi